साकार होती औद्योगिक विकास की संकल्पना

शून्यता के माहौल में उद्योगों की कल्पना दिवास्वप्न जैसी थी। कृषि पर आश्रित पूर्वांचल का यह भू-भाग 1975 में औद्योगिक नक्शे पर कहीं नजर नहीं आता था। देश-दुनिया के उद्यमी, आना तो दूर यहां का नाम लेने से कतराते थे। निराशा भरे इस माहौल को बदलने का जो संकल्प गीडा की स्थापना के रूप में लिया गया, वह 30 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद अपनी संकल्पना को सिद्ध कर पाया। बदलाव की इस यात्रा के साक्षी रहे दैनिक जागरण ने उतार-चढ़ाव भरे इस दौर को न केवल देखा बल्कि जीया भी। गोरखपुर की औद्योगिक यात्रा पर मुख्य संवाददाता **रजनीश त्रिपाठी** की रिपोर्ट...

रात में जगमगाता फर्टिलाइजर परिसर • जागरण

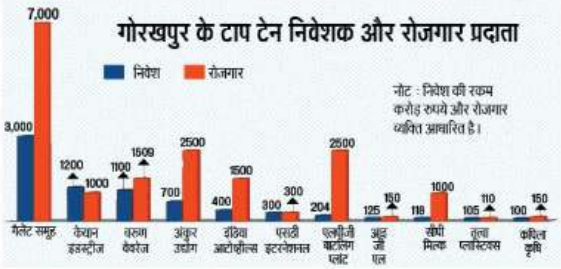

आजादी के बाद भारत में आर्थिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव नगण्य ही रहा। एक दशक बीत गए लेकिन कुछ चीनी मिलों और एक जूट मिल के अलावा अधिकांश आबादी कृषि पर ही निर्भर रही। हथकरघा, बुनकरी, लकड़ी, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प जैसे स्थानीय स्तर पर प्रचलित कुछ कुटीर उद्योगों को छोड़ दें तो बाकी उद्योग सीमित मात्रा में ही विकसित हो पाए। 1960 से 1970 के दशक में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की तो इस दौरान 1967 में औद्योगिक आस्थान और तीन साल बाद औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई। जिले में फ्लोर मिल, तेल मिल और लकड़ी प्रसंस्करण की इकाइयों के रूप में कुछ छोटे और मझौले उद्योग स्थापित होने लगे। कच्चे माल और उद्योगों के विस्तार के लिए भूमि की अनुपलब्धता, बाजार और बिजली, परिवहन तथा तकनीकी शिक्षा जैसे बुनियादी ढांचों की कमी के चलते ज्यादातर उद्योग बंद हो गए या अपेक्षानुरूप विकास नहीं कर सके। दम तोड़ते औद्योगिक विकास के सपने को आक्सीजन दिया 1969 में स्थापित गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने ने, जो बाद में इफको का हिस्सा बनकर इस क्षेत्र के सबसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से एक बन गया। उसके बाद लगभग एक दशक तक गोरखपुर में औद्योगिक हालात लगभग स्थिर रहे। स्थापित उद्योग किसी तरह घिसटते हुए चलते रहे। कुछ बंद भी हुए।

1983 में चेंबर आफ इंडस्ट्रीज की स्थापना कर एसके अग्रवाल जैसे युवा उद्यमियों ने सुविधा संपन्न औद्योगिक क्षेत्र बनवाने का सपना देखा। आज का गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) उसी सपने का मूर्त रूप है। देश में उदारीकरण का दौर आया तो गोरखपुर में भी बदलाव की उम्मीद जगी। इसको पंख लगाया यहां के प्रमुख उद्यमी चंद्रप्रकाश अग्रवाल ने, जिन्होंने गैलेंट इस्पात की नींव रखी।

आर्थिक सुधार और उदारीकरण वाले 1990 से 2005 के दौर में देश में निजी निवेश को तो बढ़ावा मिला, लेकिन इसका प्रभाव बड़े शहरों तक सीमित रहा। पूर्वांचल और गोरखपुर को इसका फायदा कम ही मिला। प्लास्टिक प्रोसेसिंग, फर्नीचर निर्माण, परिधान निर्माण जैसे कुछ लघु और मध्यम उद्योग गोरखपुर में उभरे लेकिन उनको बड़े फलक पर पहचान नहीं मिल सकी। कुशल श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय और आइटीआइ संस्थानों ने कुछ तकनीकी प्रशिक्षण शुरू किया, लेकिन वह इस स्तर तक नहीं पहुंचा, जिसकी कल्पना यहां के उद्यमी कर रहे थे। इसी बीच गोरखपुर खाद कारखाना के बंद होने से औद्योगिक विकास को बड़ा झटका लगा।

उद्यमियों के संघर्ष का साक्षी गीडा

: गोरखपुर के औद्योगिक विकास की नींव गीडा की स्थापना से पड़ी। चेंबर आफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष ई. एसके अग्रवाल बताते हैं कि हमने प्रदेश एवं केंद्र स्तर पर पहली लड़ाई गोरखपुर को पिछड़े जनपदों की श्रेणी में शामिल करने की शुरू की। भारत सरकार ने 1986 में पिछड़े क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए बैजल कमेटी का गठन किया। चेंबर आफ इंडस्ट्रीज ने तत्कालीन सांसद मदन पांडेय के सहयोग से इस कमेटी के समक्ष गोरखपुर मंडल के पिछड़ेपन के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। प्रदेश सरकार के निर्देश पर तत्कालीन अपर निदेशक उद्योग राकेश मित्तल, तत्कालीन संयुक्त निदेशक उद्योग मनोज कुमार और चेंबर आफ इंडस्ट्रीज के तत्कालीन सचिव के तौर पर उन्होंने महाराष्ट्र के नासिक जाकर, वहां के औद्योगिक विकास का अध्ययन किया। उसके बाद अपना प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा। इसमें गोरखपुर के औद्योगिक विकास के लिए, गोरखपुर व सहजनवां के बीच दो हजार एकड़ भूमि उद्योगों के लिए उपलब्ध कराने की बात शामिल थी। इसी बीच बैजल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने अगले पांच वर्ष में 100 ग्रोथ सेंटर और तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने पूर्वांचल में नोएडा की तर्ज पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा की। भारत सरकार ने 1988 में प्रथम चरण में 61 ग्रोथ सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसमें छह ग्रोथ सेंटर उत्तर प्रदेश के हिस्से आए। 1988 में ही प्रदेश में ग्रोथ सेंटर के चयन के लिए 18 जनपदों की सूची जारी की गई, जिसमें गोरखपुर शामिल नहीं था।

खाद कारखाना परिसर में स्थापित मशीनें • जागरण

चेंबर आफ इंडस्ट्रीज और सांसद मदन पांडेय ने मुख्यमंत्री से इस पर आपत्ति जताई, जिसके फलस्वरूप अंतिम चरण में गोरखपुर का चयन भी कर लिया गया। 1989 को प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना में 1200 एकड़ भूमि में प्रसार और प्रथम चरण में 564 एकड़ भूमि विकसित करने का प्रस्ताव किया गया। भारत सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 1989 को सहजनवां स्थित 38 औद्योगिक विकास इकाइयों को स्वीकृति प्रदान करने के बाद 30 नवंबर 1989 को औपचारिक रूप से गीडा की स्थापना की गई। भूमि का अधिग्रहण न होने और किसी अधिकारी की नियुक्ति न होने से इस परियोजना को लेकर प्रशासन व उद्यमियों के मन में शंका बनी रही। चेंबर आफ इंडस्ट्रीज के लगातार प्रयासों का परिणाम रहा कि 1990 में प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में गीडा को शामिल कर लिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के गोरखपुर आगमन पर चेंबर ने उद्योग लगाने के इच्छुक 791 उद्यमियों की सूची उन्हें सौंपी।

इसी साल वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बाबूराम ने गीडा के प्रथम मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। कई विभागों ने मिलकर गीडा की स्थापना के लिए स्थल का चयन करके अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हुई। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने गीडा के शिलान्यास कार्यक्रम में पांच करोड़ रुपये का चेक सौंपा, जिसके बाद कार्य में तेजी आई। तत्कालीन सांसद महंत अवेद्यनाथ के हस्तक्षेप से किसानों के हितों का ध्यान करते हुए भूमि का अधिग्रहण सफलतापूर्वक कर लिया गया।

गीडा की प्रमुख योजनाएं

- गारमेंट पार्क
- प्लास्टिक पार्क
- फ्लैटेड फैक्ट्री
- आइटी पार्क
- औद्योगिक गलियारा
- कालेसर योजना
- इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

योगी बने मुख्यमंत्री तो शुरू हुआ नया युग

औद्योगिक क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ 2017 के बाद, जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री योगी की पहल से गोरखपुर में औद्योगीकरण की रफ्तार अचानक तेज हो गई। बंद हो चुके फर्टिलाइजर कारखाने का 2021 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोबारा उद्घाटन किया, जिसका संचालन हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेस-वे के अलावा धुरियापार में नए औद्योगिक कारिडोर की रूपरेखा तैयार हुई। एयरपोर्ट के विस्तार के अलावा गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक नए एक्सप्रेस-वे तथा गोरखपुर से शामली तक एक्सप्रेस-वे का काम शुरू हुआ तो देशभर के उद्यमियों को गोरखपुर उपयुक्त औद्योगिक गंतव्य के रूप में नजर आने लगा। पिछले पांच वर्षों की बात करें तो टेक्सटाइल, मेडिकल, स्टील सेक्टर में 50 से अधिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। फ्लैटेड फैक्ट्री, प्लास्टिक पार्क, आइटी पार्क व लाजिस्टिक पार्क का काम तेजी से चल रहा है। लंबे समय से चली आ रही कामन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की स्थापना की योजना को भी मंजूरी मिल गई है। औद्योगिक गलियारे के चलते लैंड बैंक की समस्या भी समाप्त हो गई है। वरुण बेवरेज, अंकुर सरिया फैक्ट्री, गैलेंट सीमेंट फैक्ट्री गोरखपुर के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे रहे हैं।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय • जागरण

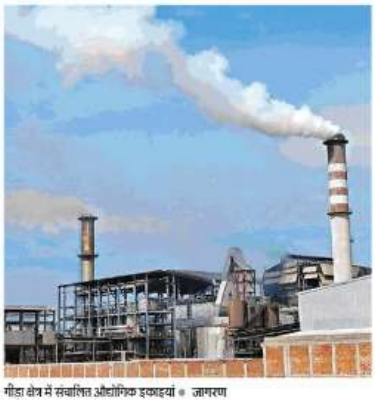

गीडा क्षेत्र में संचालित औद्योगिक इकाइयां • जागरण

वरुण बेवरेज का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ • जागरण आर्काइव